6 उत्तर भारतीय राज्यों ने व्यवसाय में सुगमता पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया

- *28 फरवरी 2019 है राज्यों द्वारा बिज़नेस रिफार्म एक्शन प्लान (ब्रैप)– 2019 के कार्यान्वयन की अंतिम तिथि*
- *ब्रैप 2019 के तहत रैंकिंग के लिए फीडबैक होगा प्रमुख मानदंड*
- *वर्ष 2014 में 142 की रैंकिंग से, भारत ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की विश्व रैंकिंग में 77वें स्थान पर पहुंचा*
- *वर्ष 2017–18 में 17 राज्यों ने 90 प्रतिशत् से अधिक सुधारों को लागू किया*

राज्य सरकार ऑनलाइन पोर्टल – निवेश मित्र पर नई औद्योगिक सेवाओं को जोड़ने की कार्यवाही कर रही है – मुख्य सचिव एवं आई.आई.डी.सी.

उद्योग बंधु प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से बिज़नेस सुधारों को मण्डल स्तर तक ले जा रहा है – प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास

लखनऊ, 20 दिसम्बर 2018:

राज्यों में कारोबारी माहौल में सुधार करने के लिए अपने कार्यक्रम के तहत **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)**, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **विश्व बैंक समूह** के सहयोग से आज यहाँ उद्योग बंधु कार्यालय में **"बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (ब्रैप)–2019 के कार्यान्वयन दिशानिर्देश एवं फीडबैक पद्धति"** पर उत्तर भारतीय क्षेत्र के राज्यों हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त **जम्मू–कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड** और **हिमाचल प्रदेश** के अधिकारियों ने इस एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

ब्रैप–2019 के तहत राज्यों द्वारा **80 संस्तुति बिन्दुओं** का कार्यान्वयन किया जाना है। कार्यशाला में सूचित किया गया कि इस बार **उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया (फीडबैक) राज्यों की रैंकिंग का मुख्य मानदण्ड होगा** और यूज़र्स से लागू किए गए सभी सुधारों पर प्रतिक्रिया ली जाएगी। इन सुधार बिन्दुओं के कार्यान्वयन की **अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2019** है।

कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए **मुख्य सचिव एवं अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी)–डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय** ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के सिंगल विण्डो पोर्टल–निवेश मित्र को लगातार सुदृढ़ करके व्यवसाय हेतु वातावरण को सुगम बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि निवेश मित्र पर वर्तमान में उपलब्ध 20 विभागों की 70 सेवाओं के अलावा सरकार द्वारा इस ऑनलाइन पोर्टल पर नई औद्योगिक सेवाओं को जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। **आईआईडीसी ने कहा** कि इसके अतिरिक्त हम उद्यमियों की समस्याओं को हल करने के लिए उनके के साथ नियमित संवाद–सत्र आयोजित करते हैं।

डॉ पाण्डेय ने कहा कि राज्य सरकार के नए कदमों और निवेश अनुकूल नीतियों के प्रति निवेशकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया इस दिशा में राज्य सरकार के सफल प्रयासों की साक्षी है।

विश्व बैंक के प्रतिनिधि श्री हर्ष झांजरिया ने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार एक गतिशील प्रक्रिया है। **उन्होंने कहा** कि भारत में पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सिफारिशों के वास्तविक कार्यान्वयन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। **उन्होंने बताया** कि **वर्ष 2017–18 में 17 राज्यों ने 90 प्रतिशत् से अधिक सुधारों को लागू किया है।**

विदित हो कि **वर्ष 2014 में 142वीं रैंकिंग से भारत ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की विश्व रैंकिंग में 77 वें स्थान पर पहुंच गया**, इतनी कम अवधि में किसी भी देश द्वारा की गई यह सबसे ज्यादा प्रगति है। अब **भारत दक्षिण एशियाई देशों में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में पहले स्थान पर है।**

इस तथ्य पर बल देते हुए कि उत्तर प्रदेश द्वारा व्यावसायिक सुधार बिंदुओं को लागू करने में 92.89 प्रतिशत् स्कोर के साथ 'अचीवर स्टेट' श्रेणी हासिल की है, **प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास – श्री राजेश कुमार सिंह ने बताया** कि उद्योग बंधु द्वारा मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से बिज़नेस सुधारों के प्रति सरकारी अधिकारियों और उद्यमियों को जागरूक किया जा रहा है। इस तरह की कार्यशालाओं को अभी तक राज्य के 14 मण्डलों में आयोजित किया गया है।

इससे पूर्व प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए **सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बंधु – श्री संतोष कुमार यादव** ने कहा कि बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन में सभी राज्यों के अनुभव को साझा करने से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सकारात्मक योगदान मिलेगा।

इस अवसर पर डीआईपीपी प्रतिनिधियों द्वारा बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान–2019 पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया और प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से सुधार कार्य योजना के तहत प्रतिक्रिया प्रणाली के संबंध में अपने प्रश्न उठाए, जिनका संतोषजनक रूप से समाधान किया गया।